देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 20.09.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया।
- आईआईटी रुड़की में उन्नत भारत अभियान के समन्वयकों के लिए कार्यशाला का आयोजन। विशेषज्ञों ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए टिकाऊ और विविध कृषि पद्धतियों पर ज़ोर दिया।
- देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल बने निक्षय मित्र, टी.बी मरीज को गोद लेकर पोषण का जिम्मा संभाला।
- प्रदेशभर में ''स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान'' के तहत वृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं।

.....

मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बुनियादी सुविधाओं की बहाली के कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रूद्रप्रयाग जिले में आपदाग्रस्त बसुकेदार तहसील के छेनागाड, तालजामण, उच्छोला, डांगी और बडेथ गाँवों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत दी जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष रुद्रप्रयाग सहित प्रदेश में आपदा के कारण काफी नुकसान हुआ है और सरकार आपदा को लेकर हर मोर्चे पर मुस्तैदी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री / चमोली

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का भी जायजा लिया और प्रभावितों का हाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत कार्यो की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुक़सान का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5–5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक भी प्रदान किये। श्री धामी ने आपदा प्रभावित कुंतारी लगा फाली और कुंतारी लगा सरपाणी का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही धुर्मा, मोख, कुंडी, बांसबारा और मोखमल्ला गांवों का हवाई सर्वेक्षण कर आपदा से नुकसान और राहत कार्यों का जायजा लिया।

उन्होंने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पेयजल की सुचारू आपूर्ति और सभी क्षेत्रों तक सड़क संपर्क बहाल करने के काम को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए।

कार्यशाला

आईआईटी रुड़की स्थित उन्नत भारत अभियान– यूबीए के क्षेत्रीय समन्वय संस्थान द्वारा उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यूबीए समन्वयकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समन्वयकों, विशेषज्ञों और सामुदायिक नेताओं ने नवाचार, पारंपरिक ज्ञान और उद्यमिता के माध्यम से सतत ग्रामीण विकास पर विचार–विमर्श किया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए टिकाऊ और विविध कृषि पद्धतियों पर ज़ोर दिया। कार्यशाला में आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर कमल किशोर पंत ने कहा कि उन्नत भारत अभियान की भावना ज्ञान, प्रौद्योगिकी और सतत प्रथाओं के साथ गाँवों को सशक्त बनाने में निहित है। उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की नवाचार–संचालित पहलों के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पद्मश्री श्री सेठपाल सिंह ने कहा कि सच्चा विकास गाँवों से शुरू होता है और कृषि में विविधता व पारंपरिक ज्ञान को अपनाकर किसानों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित की जा सकती है। तकनीकी सत्रों में कृषि विविधीकरण, शहद प्रमाणीकरण एवं खाद्य सुरक्षा, जैविक खेती, मौसम पूर्वानुमान, पर्यावरण–ग्राम अवधारणाएँ और आत्मनिर्भर गाँवों के लिए उद्यमिता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञ वक्ता प्रोफेसर एन.के. नवानी ने बताया कि राष्ट्रीय मधु प्रमाणीकरण एवं खाद्य सुरक्षा केंद्र, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने 'मधु क्रांति' पहल के तहत किसानों को दिए जा रहे प्रशिक्षण, उपकरणों पर सब्सिडी और प्रसंस्करण सुविधाओं पर प्रकाश डाला।

जिलाधिकारी निक्षय मित्र

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने निक्षय मित्र बनकर टी.बी से ग्रसित टर्नर रोड निवासी एक महिला को गोद लेकर उसके इलाज और पोषण की पूरी जिम्मेदारी ली है। इसके तहत जिलाधिकारी ने आज महिला को पोषण किट प्रदान की। टीबी उन्मूलन के लिए उपचार से ठीक होने तक महिला को मुफ्त इलाज और पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि टीबी मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए सबकी सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि टी.बी का इलाज संभव है। अगर सही समय पर उपचार और दवाओं का सेवन किया जाए और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो क्षय रोगी स्वस्थ हो जाते है। जिलाधिकारी ने कहा कि निक्षय पोषण योजना के तहत सरकार की ओर से टीबी मरीजों को पोषण के लिए एक हजार रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार

प्रदेशभर में ''स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार अभियान'' के तहत वृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। शिविरों में गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, हाइपरटेंशन, डायबटीज, कैंसर परीक्षण, गर्भवती महिलाओं को परामर्श, बच्चों का टीकाकरण, टीबी स्क्रीनिंग, नि–क्षय मित्र पंजीकरण, रक्तदान आदि किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान" के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अभियान से महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न रोगों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है।

चलो जीते हैं स्क्रीनिंग

राजधानी देहरादून स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, आईएमए में मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं पर आधारित फिल्म 'चलो जीते हैं' की आज विशेष स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य मामचन्द ने कहा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना और समाज के लिए समर्पित रहना है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिखाती है कि अगर हम समाज के प्रति संवेदनशील हों, तो छोटी उम्र में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

वहीं, स्क्रीनिंग के बाद छात्राओं ने कहा कि व्यक्ति छोटा–बड़ा नहीं होता, उसके विचार बड़े होते हैं और यह फिल्म काफी प्रेरणादायक है।

लगभग तीस मिनट की इस फिल्म का विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बचपन के संघर्ष और समाजसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर केंद्रित है। इसके अलावा फिल्म, स्वामी विवेकानंद के दर्शन को एक सशक्त श्रद्धांजलि भी है।

नुकसान समीक्षा

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को पुनर्निर्माण और सुरक्षात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर आपदा के चलते नालों, पुलों, सड़क किनारे सुरक्षा दीवारों आदि के कार्यों का त्वरित पुनर्निर्माण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय जनता को राहत पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए विभागीय अधिकारी बिना किसी देरी के कार्ययोजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करें। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सभी प्रभावित स्थलों का मौके पर सर्वे करने और शीघ्र विस्तृत

आकलन तैयार कर शासन को भेजने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकलन तैयार होने के बाद शासन स्तर पर आवश्यक बजट की स्वीकृति दिलाकर पुनर्निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरु किए जाएंगे।

.....